अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कीम

2854. **डा० रत्नाकर पाण्डेय**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की छोटी-छोटी कालोनियों में जिनकी आबादी मात्र 200-250 व्यक्तियों की है, रह रहे हरिजनों और आदिवासी लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कोई स्कीम बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे गांवों और कालोनियों की संख्या कितनी हैं, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चुना गया है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यवाही योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुल जनसंख्या वाले राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, में 200 अथवा इससे अधिक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली 10,000 बस्तियों में सेवा पैकेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभ के इस पैकेज में (i) यदि नजदीक में कोई प्राइमरी स्कूल न हो तो भवन सहित और गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना (ii) हैंडपंप/पीने के पानी के स्रोत का प्रावधान (iii) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत गलियों में प्रकाश व्यवस्था तथा गरीब परिवारों के लिए एकल प्वाइंट प्रकाश सयोजन (iv) अ०ज०जा० के छोटे आंशिक किसानों के लिए सिंचाई हेतु कुंए प्रदान करना जिनके पास सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, तथा (v) भूमि के स्वामित्व की जांच पड़ताल करना तथा जहां कहीं आपेक्षित हो, उन्हें पुनः बहाल करना आदि शामिल है। इन राज्यों में 10,000 बस्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदला जाना

2855. **डा० अबरार अहमद खान**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए क्या-क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदले जाने के लिए पात्र है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने की आवश्यकता को स्वीकार करती है ; यदि हां, तो राजस्थान विश्वविद्यालय को कब तक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) नीति के एक मामले के तौर पर, केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है ; अतः राजस्थान विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Pusa Public Schools in Delhi

2856. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pusa Public School is being run in more than one locality in Delhi;